ISSN 2231-1629
Knowledge Resonance
A Half Yearly National Peer-Reviewed & Indexing with SJIF Impact Factor Research Journal
IMPACT FACTOR 8.072

भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन के अंतर्राष्टोय आयाम

डॉ. जितेन्द्र पाटीदार
राजनीति विज्ञान
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा, जिला नीमच म.प्र.

सारांश :
भारतीय विदेश नीति में पंचशील की नीति इसके नैतिक व शांति स्थापना के मूल्यों की घातक है। अर्थात नेहरू जी ने विश्व शांति को केवल आदर्श ही नही बल्कि इसे व्यवहारिक रूप पदत करना चाहते थे इसलिए उन्होनें शांति पूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। और प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्रहित है और भारत इसका अपवाद नही है अर्थात भारत ने अपने राष्ट्रहितों को सुरक्षित रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को उन्नत करने व राष्ट्रों के मैत्रीपूर्ण सहिष्णुता संबंधों को बनाये रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न करने में सदैव प्रयासरत रहा है। यह भारतीय विदेश नीति की विशेषता है कि संकट की स्थिति में अपने आप को उबारा और किसी भी देश की विदेश नीति एक विशिष्ट आंतरिक व बहाय वातावरण के स्वरूप द्वारा काफी हद तक निर्धारित होती है । और स्वतन्त्र विदेश नीति का निर्माण करना । तटस्थता नही बल्कि गुण–दोष के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबधों का मूल्यांकन करना शीतयुद्ध भय का परिणाम है। अर्थात पंचशील के सिद्धांत के आधार पर सहयोग और सहिष्णुता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निर्माण करना होता है। और भारत की विदेश नीति भारत की विदेश नीति समनाता स्वत्रता बंधुत्वता व लोकतांत्रिकता के सिद्धान्तों पर आधारित है।

मूल शब्द :
शांति का बदलता स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय मूलभूत सिद्धान्त, भारत की विदेश नीति

प्रस्तावना :

किसी भी अन्य देश की तरह भारत कि विदेश नीति अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बनाने और सभी राष्ट्र में अपनी भूमिका बढाना एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करने की परिकल्पना करती है । और वर्ष 2021 की विदेश नीति के उद्देष्य को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों विडम्बना जैसी समस्याऔ से गुजरना पड़ता है। और दक्षिण एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में चीन का उदय हुआ। और भारत के पड़ोसी देशों पर इसका बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ी निवेश समक्षौते पर हुई चर्चाओं में ''कोविड–19'' महामारी के बाद चीन में अलग थलग पड़ने से जुड़े मिथक को भी समाप्त किया है । साथ ही इसने चीन की स्थिति को अधिक मजबूत किया और इसके अलावा अमेरिका के साथ बढते समन्वय की तरह भारतीय विदेश नीति के कई निणयों के साथ इसके संबधों को कमजोर किया है। और भांति संतुलन के लिए भारत को विदेश नीति की चुनोंतियों से निपटने के साथ उपलब्ध अवसरों का सावधानी पूर्वक सामावित करने की अवश्यकता होगी और आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय का युग है । अंतर्राष्ट्रीय संबधों में राष्ट्रों की पारम्परिक आत्मनिर्भरता वह सच्चाई है जिसमें कोई देश बच नही सकता और आज विश्व के सभी देश अपने अपने लिए प्रयासरत है और प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी संबंधों में स्वतन्त्र विदेश नीति का कियान्वयन करता है और विश्व के अधिकांश देश यह प्रयास करते हुए देखे जाते है। कि उनकी विदेश नीति का अंतर्राष्ट्रीय संबधों पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इसलिए सभी देश अपने अपने राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय हितों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते है। वे अपने विदेशो में राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों को गौण स्थान पर रख देते है और जो अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में खटास पैदा करते है अर्थात भारत भी इसका अपवाद नही है । भारत की अपने स्वतंत्रता व राष्ट्रीय हितों का अंतर्राष्ट्रीय हितों से सामंजस्य स्थापित करने वाली विदेश नीति है। और किसी भी स्वतंत्रता व प्रभुसता सम्पन्न देश की विदेश नीति के मूल रूप में उन सिद्धांतों हितों तथा लाखों का समूह होता है। जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश में साथ संबंध स्थापित करने उन सिद्धान्त हितों व तथ्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है की किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति उसकी अन्तरिक नीति का ही एक भाग होता है जिसे कियावित करना सरकारी व गैर सरकारी अभिकरणों का प्रमुख कर्तव्य होता है। और किसी भी देश की विदेश नीति इतिहास से गहरा संबंध रखती है और भारत की विदेश नीति भी इतिहास और स्वतन्त्र अन्दोलन से संबंध रखती है। और ऐतिहासिक विरासत के रूप में भारत की विदेश नीति आज उन अनेक तथ्यों को समेटे हुए है जो कभी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से उपजे थें। बल्कि हमारी विदेश नीति ऐसी है जो अतीत के सुन्दर इतिहास और राष्ट्रीय आन्दोलन से सम्बधित है । इसका विकास उन सिद्धान्त के आधार पर हुआ जिसकी घोषण हम अतीत में कर चुके है । इसका तात्पर्य यह है की भारत की विदेश नीति के निर्माण में परम्परा तथा स्वतन्त्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और विदेश नीति का संबंध दूसरे राष्ट्रों से संबंध बनाऐं रखने की नीति से होता है। ये संबंध इस बात से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते है कि उस राष्ट्र में बनाए जा रहे संबंधो संन्धियों या

समझौंतों के प्रति राष्ट्रो के उन संबंधों के बारे में कैसा पर्यावरण है और इसका सीधा अर्थ यह निकलता है। कि किसी भी राष्ट्र के पर्यावरण या परिवेश से प्रभावित होती है। और भारत की विदेश नीति भी इसका अपवाद नही है, भारत की विदेश नीति घरेलू तथा बाह्य परिवेश से प्रभावित होते हुए अनेक उतार चढ़ावों से गुजरती है। कई बार तो बाह्य परिवेश से घरेलू पर्यावरण को भी प्रभावित करके भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव डाला है। इस संदर्भ में सीमा विवाद, नही जल विवाद, सुरक्षा व्यवस्था, हिन्द महासागर की समस्या तिब्बत का प्रश्न क्षेत्रिय सहयोग संगठन शीत युद्ध रंगभेद नीति पर स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के वातावरण ने जहा भारत की विदेश नीति को गुटनिपेक्षता का आधार प्रदान किया है, वही शीत युद्ध के अंत में उसे विदेश नीति निर्माताओं को बाध्य किया कि वे गुटनिपेक्षता की मूल संकल्पना में परिवर्तन करे और अधिक उदरीकरण की नीति अपनाएं तथा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से परमाणु नीति में भी परिवर्तन करें इसी कारण सोवियत संध विघटन तथा शीत युद्ध के अंत के बाद भारत की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला । इस प्रकार भारत की विदेश नीति अन्य देशों के साथ राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से किये जाने वाले कार्यकलापों संवेदनशीलता के साथ समन्वय किया जा सके।

अंतराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति :

सभी देशों की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य भी राष्ट्रीय हित है। व अपने राष्ट्र के हित तथा अपने देश के आदर्शों को ध्यान में रखकर तथा अंतर्राष्ट्रीय हित में समन्वय स्थापित करते हुए हमारे देश की विदेश नीति के कुछ सिद्धान्त निधारित किए है इन्ही को भारत की विदेश नीति की विशेषताएं या आधार के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत की विदेश नीति को अंसलग्नता की नीति के नाम से परिभाशित किया जाता है। और भारत की असंलग्नता की विदेश नीति का प्रमुख घोषणा पत्र एंव मूलभूत निर्णायक सिद्धान्त है। अंसलग्नता को समय समय पर पॉलिसी ऑफ न्यूट्रीलिटिव नान इन्वाल्वमेंट तथा महाशिक्तयों के मध्य बराबर की दूरी बनायें रखने की नीति से जाना जाता है। और अंसलग्नता विश्व राजनीति में स्वतंत्र नीति के निर्धारण एंव उस पर अमल करने की क्षमता प्रदान करता है। और भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव किया है। और शीत युद्ध कि समाप्ति के बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्याख्या कायम हो गई। और वैश्विकरण अथवा भूमडलीकरण के चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा का समापन होने की कगार पर है। ऐसे प्रत्येक राश्ट्र आर्थिक हितों को प्रधानता देने में लगा है। जिससे परिवर्तन परिवेश में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य होने चाहिए तथा इन लक्ष्यों की पूर्ति वर्तमान समसमायिक विश्व में पुरी किया जा सकता हैं। और भारत की विदेश नीति को बदलते संबंधों के आधार पर पुनर्विचार करने के लिए एक नई दिशा प्रदान किया जाना चाहिए ।

बदलती भारतीय विदेश नीति :

- भारत की वर्तमान विदेशनीति की सबसे खास विशेषता यह है की इसमें पूर्व की सभी नीतियों की अपेक्षा जोखिम लेने की प्रकृति सबसे अधिक है।
- भारत अपनी दशको पुरानी सुरक्षात्मक नीति को बदलते हुए कुछ हद तक आक्रमक नीति की और अग्रसर हो रहा है।
- कई जानकारों का मानना है कि भारत की वर्तमान विदेश नीति में विचारों और कार्यवाही की स्पष्ट दिखाई देती है।
- बदलते वैश्विक राजनीतिक परिवेश में भारत अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किसी भी औपचरिक समूह पर निर्भरता को सीमित कर रहा है।
- भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। और अमेरिका तथा रूस के साथ भारत के संबंधों जैसे कई तथ्यों का उदाहरण है।

भारत की विदेश नीति व वर्तमान चुनौतियां :

देश की विदेश नीतियों के रणनीतिक उददेश्य तथा भौगोलिक निवेश अंतर्राष्ट्रीय संवाद की रूपरेखा को मोटे तौर पर परिभाषित करते हुए विदेश नीति लगातार बदलती रहती है। उसे घरेलू बाध्यताओं तथा वैश्विक संपर्क की संभवनाओं एवं क्षमताओं के अनुसार और भी दुरूस्त किया जाता है। ताकि उसके राष्ट्रीय हितों को तत्कालीन सरकार की धारणा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तरीके से साझा जा सके । और गुट निपेक्षता हो या प्रमुख शक्तियों को चुनकर उनके साथ गठबंधन करना हो और राष्ट्रीय हित के मामलों तथा विदेश नीति में मूल उद्देश्य पर आजादी के बाद से अभी छोटे या लंबे समय में संभावित लाभों के मुताबिक परिर्वतन किए गए हैं। किंतु मई 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सत्तासिन होने के बाद से विदेश नीति में विस्तार की शैली तरीकों तथा घटकों में नाटकीय परिर्वतन हुआ है। इसके परिणाम से कुछ लोग असहमत हो सकते है। किन्तु परिवर्तन सामने दिख रहै है। और विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नही होगी कि अपने पड़ोसियों तथा आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत दूरवर्ती पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को दुरूस्त करना भी चुनोती होगी क्योंकि वे शक्तिया अपना अपना प्रभाव जमाने के लिए होड़ करती रहती है। तथा किसी न किसी जरिए यह काम करना चाहती है। जब की आकार में आर्थिक एंव सैन्य शक्ति मानव संसाधन तथा राजनीतिक लाभ के कारण भारत एक ऐसी भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है । जिससे सता में संसोधन हो सके और भारतीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को दुनिया में एक सम्मनित और जिम्मेदार अग्रणी भाक्ति बनाने का आहवान किया और

अपनी विदेश नीति को फिर से विकसित करने के लिए निर्णय लेने की यह कवायद देश की बढती ताकत के साथ–साथ राष्ट्र की शिष्टता से पहले अपने नए आत्मविश्वास को प्रकट करती है की किस तरह शीर्ष भारतीय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक मामलों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाने का कार्य करे ।

भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धान्त :

पंचशील सिद्धान्त उल्लेखनीय है कि पंचशील सिद्धान्त को सर्वप्रथम वर्ष 1954 में चीन के तिब्बत देश तथा भारत के मध्य संधि करने के लिए प्रतिपादित किया गया और बाद में इसका प्रयोग वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है । जैसे :–

- एक दूसरे की क्षेत्रिय अखड़ता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान ।
- पारस्परिक आक्रमण न करना ।
- परस्पर हस्तक्षेप न करना ।
- समता और आपसी लाभ ।
- शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाना।

भारत की विदेश नीति में राज्यों की बढ़ती भूमिका

मई 2021 में भारत के कई राज्यों ने कोविड वैक्सीन की कमी को देखते हुए विदेशी कम्पनियों से वैक्सीन की आपूर्ति के लिए टेण्डर प्रकाशित किए थे । यह विश्व बाजार में राज्य की भागीदारी का नया उदाहरण है। इससे एक बार फिर यह प्रश्न सामने आ गया है कि आखिर वैश्विक व वैदेशिक मामलों में राज्यों की क्या भूमिका है। वैसे तो भारत में विदेश नीति का निर्माण व संचालक एक संमीप विषय है। जो केन्द्र सरकार के राज्यों की बढ़ती भूमिका के उदाहरण सामने आ रहे है। अतः इस भूमिका के स्वरूप को समझाना आवश्यक है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। जिसके अंतर्गत संविधान की सातवी अनुसूची में केन्द्र व राज्यों के बीच भाक्तियों का बटवारा किया गया है इसके अंतर्गत सभी वैदेशिक मामला जैसे विदेश नीति कूटनीतिक संबंध युद्ध व शांति समझौता आदि । को स्थान दिया गया है। और संघसूची पर कानून बनाने तथा प्रशासन का अधिकार केन्द्र सरकार को प्राप्त है। इतना ही नही वैदेशिक मामलों में संविधान के अंतर्गत केन्द्र सरकार को कतिपय अन्य अधिकार भी दिए गए है उदा. : के लिए संविधान अनु 253 के अंतर्गत संसद को किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है। इससे स्पष्ट है कि कानूनी रूपी से वैदेशिक मामलों में केन्द्र सरकार का एकाधिकार होता हैं।

निष्कर्ष :

विदेश नीति एक गतिशील प्रकिया है और विश्व में एक उन्नतशील भाक्ति बनने के लिए भारत के नए उत्तर दायित्वों के साथ–साथ इसकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। सन् 1991 के बाद से भारतीय विदेश नीति गटनिपेक्षता के मूल सिद्धान्तों से विचलित हुए बिना अपने दृष्टिकोण में अधिक यथार्थवादी हो गई है। राजनीतिक दृष्टि से जब भारत का ध्यान अपने पड़ोसी देशों विशेष रूप से चीन और पकिस्तान पर केन्द्रित हो गया है। और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आन्तरिक विवादों को जन्म लेने से रोकना और भारत द्वारा अपने पड़ोसियों से विवादों का समाधान करना इस रणनीति के अपरिहार्य भाग है। अर्थात सभी तत्व भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्धारण है। इन सभी मुख्य कारको ने भारत की क्रियाशीलता को एक नया आकार का क्रियान्वयन किया जाता है। और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिदृश्य के कारण भरत की विदश नीति में किन विरचारों को अपनाया गया था। उनमें समय–समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसी प्रकार भारत की विदेश नीति में व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी परिस्थिततियों में अपने राष्ट्रीय हितों को साकार करते हुए अपने लक्ष्य की और बढ़ते रहे है। और भारतीय राजनीति नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व मामलों में अपनी भूमिका की कल्पना करता है। इसी संवेदनशील के आधार कार्य किया जाता है। और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बदलती वास्तविकताओं के बीच यदि भारत मात्र एक आकांक्षी भागीदारी के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है। तो उसे अपनी विदेश नीति के साथ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। और इसी संवेदन भीलता के साथ कार्य करना होगा ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- *त्रिपाठी, डॉ सदानन्द, अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका प्रकाशक ए. बी. रोड़ जयपुर सन 2000 पृ.09*
- *गुप्ता, आर सी केसवानंद, भारतीय शासन व राजनीति प्रकाशक, नई दिल्ली सन् 1999 पृ. 65*
- *फडिया, जैन, भारतीय भाासन व स्थानीय प्रशासन प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो, आगरा सन 1899 पृ. 10*
- *त्रिवेदी, डॉ वी. के. राय, भारतीय सरकार एंव राजनीति प्रकाशक आर के रोड़ उदयपुर, सन 2001 पृ. 20*